भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 210*

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रसव-गृह गुणवत्ता सुधार संबंधी पहल

†*210. श्री बैजयंत पांडाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा ओडिशा में सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव-गृह गुणवत्ता सुधार संबंधी पहल (लक्ष्य) लागू की गई है, यदि हां, तो वर्ष 2025 तक इसके अंतर्गत किस प्रकार की सुविधाओं को शामिल किया गया है;
(ख) राज्य में ऐसे प्रसव-गृहों और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों का ब्यौरा क्या है जिन्हें राष्ट्रीय स्तर के 'लक्ष्य' प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं;
(ग) क्या यह कार्यक्रम जनजातीय जिलों में शुरू किया गया है और यदि हां, तो मातृ संतुष्टि सूचकांक, मृत-शिशु जन्म-दर में कमी और सेवा गुणवत्ता संकेतकों के संबंध में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और
(घ) ओडिशा हेतु 'लक्ष्य' के अंतर्गत स्वास्थ्य परिचर्या कर्मचारियों के क्षमता निर्माण अथवा प्रशिक्षण संबंधी पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 13.02.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 210* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ओडिशा राज्य सहित पूरे देश के प्रसूति कक्षों (एलआर) और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों (एमओटी) में लक्ष्य (प्रसूति कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल) को लागू किया है। इसमें मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, उप-जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं।

31 जनवरी 2026 की स्थिति के अनुसार ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय स्तर का लक्ष्य प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले प्रसूति कक्ष (एलआर) और प्रसूति ऑपरेशन थिएटर (एमओटी) निम्नलिखित हैं-

स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र का प्रकार	**राष्ट्रीय स्तर का लक्ष्य प्रमाणन प्राप्त करने वाले सुविधा केन्द्रों की संख्या-**	
	एलआर	**एमओटी**
कुल	**30**	**26**
मेडिकल कॉलेज अस्पताल	1	1
जिला अस्पताल	23	22
उप-जिला अस्पताल	4	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	2	2

(ग) लक्ष्य कार्यक्रम भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें जनजातीय जिले भी शामिल हैं, में लागू किया गया है। कार्यक्रम से हुए सुधार निम्नलिखित हैं-

- मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, जो 130 (एसआरएस 2014-16) से घटकर 88 (एसआरएस 2021-23) हो गई है।

- भारत में मृत-जन्म दर 12.5 (2020-21) से घटकर 9.4 (2025-26) हो गई है (स्रोत: जनवरी 2026 तक एचएमआईएस)।
- भारत में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत एनएफएचएस-4 (2015-16) के अनुसार 78.9% से बढ़कर एनएफएचएस-5 (2019-21) के अनुसार 88.6% हो गया है।

(घ) ओडिशा राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लक्ष्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण पहलों का विवरण निम्नलिखित है:-

- कार्यक्रम अधिकारियों और कार्यक्रम प्रबंधकों के लिए "लक्ष्य कार्यक्रम" पर राज्य स्तरीय मार्गदर्शन।
- अतिरिक्त जिला चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा), उप प्रबंधक प्रजनन बाल स्वास्थ्य (डीएमआरसीएच) और अस्पताल प्रबंधकों के लिए प्रसव कक्ष (एलआर) मानकीकरण पर राज्य स्तरीय मार्गदर्शन कार्यशाला।
- प्रथम रेफरल इकाइयों (एफआरयू) और मेडिकल कॉलेजों के अस्पताल प्रबंधकों के लिए लक्ष्य पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण।
- लक्ष्य के अंतर्गत सम्मानजनक प्रसूति देखभाल (आरएमसी) के विस्तार के लिए प्रशिक्षकों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण (टीओटी)।
- प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों, कार्यक्रम अधिकारियों और कार्यक्रम प्रबंधकों के लिए "लक्ष्य कार्यक्रम" पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण।
- जिला अस्पतालों/प्रथम रेफरल इकाइयों में सम्मानजनक प्रसूति देखभाल (आरएमसी) पर सुविधा केन्द्र स्तरीय प्रशिक्षण।

*****